

गुफा मंदिर पर 51 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोचार के साथ भूमि पूजन सम्पन्न



संत हिरदाराम नगर। लालघाटी स्थित गुफा मंदिर में आद्यवाराहपीठ वृंदावन, गुफामंदिर के महंत श्री श्री 1008 महंत रामप्रवेशदास महाराज के सानिध्य में 12 जून से 16 जून में होने वाले पंचदिवसीय नवकुण्डात्मक श्रीराम महायज्ञ एवं वृंदावन की प्रसिद्ध रासलीला मंचन का भूमि पूजन कार्यक्रम गुरुवार को गुफामंदिर में 51 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोचार के साथ अभिजित मुहूर्त में विधि विधान से संपन्न हुआ। भूमि पूजन में महापौर मालती राय, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक घर्मा, कैलाश मिश्रा, प्रियंका मिश्रा, अशोक मारण, चन्दरलाल चन्दानी, ध्याम बाबा, जगदीप घायदा, राजेन्द्र गुप्ता, प्रमोद नेमा सहित पहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

प्राकृतिक चिकित्सा का 10 दिवसीय आवासीय शिविर का शुभारंभ



संत हिरदाराम नगर। आरोग्य केन्द्र द्वारा आयोजित रोग निवारण एवं प्रशिक्षण मासिक शिविर श्रृंखला के अन्तर्गत दस दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया। इस शिविर में विभिन्न स्थानों से कई साधकगण अपकाहार एवं प्राकृतिक उपचार के साथ-साथ योगा, आयुर्वेदिक उपचार, फिजियोथैरेपी, एक्जुप्रेसर, एक्जुपंक्चर, शिरोधारा, पोटली मसाज आदि से भी लाभान्वित होने की उम्मीद से आए हैं। इस शिविर में शिविरार्थियों को प्राकृतिक उपचार, योग, उपवास एवं अपक्क आहार, रसाहार, फ लाहार के माध्यम से स्वस्थ रहने की कला सिखाई जाएगी। डॉ दिनेश यादव ने शिविरार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि इस शिविर का उद्देश्य है बिना दवा तंदुरुस्ती पाना। इस दस दिवसीय शिविर में आप अपने शरीर का शुद्धिकरण कैसे करें वो सीखेंगे। शरीर का शुद्धिकरण होना बहुत ही आवश्यक है इसलिए इस शिविर का नाम ही रोग निवारण एवं प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। इस शिविर में आप ऐसी कला सीखेंगे, जिससे आप सुखमय व स्वास्थ्यमय जीवन पा सकें। स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना। आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करेंगे तो ही आप स्वास्थ्य लाभ पा सकेंगे। बीमारी सबसे पहले मन में पैदा होती है, फिर शरीर पर प्रकट होती हैं। बीमारियों का मुख्य कारण है शरीर में गंदगी का जमा होना और बीमारियों से निजात पाने के लिए एनिमा, उपवास व अपकाहार का विशेष महत्व है। प्राकृतिक चिकित्सा में प्राकृतिक भोजन, प्राकृतिक उपचार एवं योग से शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। जितना जरूरी आपके लिए प्राकृतिक उपचार हैं उतना ही जरूरी ध्यानात्मक क्रिया हैं, इसलिए आपको ध्यानात्मक क्रिया करना आवश्यक हैं।

संत रविदास और भगवान बुद्ध की महाआरती का आयोजन

भोपाल। नवयुवक अहिरवार समाज सुधार संघ द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नया बसेरा संत रविदास मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना कर संत श्री रविदास महाराज और भगवान बुद्ध की महा आरती का आयोजन समाज के सभी बंधुओ द्वारा किया गया आज इस अवसर पर नवयुवक अहिरवार समाज सुधार संघ के अध्यक्ष गोविंद कहा मैं बताया कि बुद्ध पूर्णिमा समाज के द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है आज इसी क्रम के चलते संत रविदास महाराज और भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्प माला अर्पित कर महा आरती की गई जिसमें आज समाज के सभी वर्ग उपस्थित हुए और सभी ने भगवान बुद्ध और संत रविदास महाराज का आशीर्वाद लिया।



11 करोड़ पर्यटकों का आगमन, उज्जैन में सबसे ज्यादा 5 करोड़ 28 लाख पर्यटक पहुंचे

मग्न पर्यटन दिवस पर विशेष

भोपाल। ऐतिहासिक धरोहरों, गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, विविध वन्यजीव एवं आध्यात्मिक अनुभव के लिये देश-दुनिया में प्रख्यात मध्यप्रदेश ने साल 2023 में 11 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों का स्वागत किया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक म.प्र. में 11 करोड़ 21 लाख पर्यटक पहुंचे, जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 1 लाख 83 हजार रही। 2019 में कोविड प्रतिबंध लागू होने से पहले कुल 8,90,35,097 पर्यटकों का आगमन हुआ था। 2022 में पर्यटकों की संख्या 3,41,38,757 रही थी। प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटक उज्जैन पहुंचे, जिनकी संख्या 5 करोड़ 28 लाख से ज्यादा रही। इसी तरह प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ 10 में पांच गंतव्य धार्मिक स्थल हैं। उल्लेखनीय है कि 24 मई को मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (स्वस्वच्छ) का स्थापना दिवस है, इसी दिन को मध्यप्रदेश पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं प्रबंध संचालक म.प्र. टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि, पर्यटकों की रिकॉर्ड



वृद्धि प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास, धार्मिक पर्यटन में वृद्धि के साथ ही हमारी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और सभी आगंतुकों के लिए एक यादगार अनुभव सुनिश्चित करने के हमारे ठोस एवं समर्पित प्रयासों का प्रमाण है। अपनी सेवाओं में लगातार सुधार कर और अपने

क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और जीवत परंपराओं को प्रचारित कर हम सफलतापूर्वक अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। इसका फायदा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल रहा है और साथ ही हमारे समुदायों के विकास हेतु स्थायी अवसर सृजित हो रहे हैं।



श्रीराम कथा में भगवान राम का प्राकट्य धूमधाम से मनाया



संत हिरदाराम नगर। संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ कला रेलवे फाटक के पास स्थित श्री चित्र विचित्र हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीराम कथा के तृतीय दिवस भगवान राम का प्राकटय बड़े धूमधाम से

मनाया गया। राजा दशरथ के घर में चार पुत्रों का जन्म हुआ। सतानंद महाराज ने बताया भगवान का जन्म धरती पर क्यों होता हैं, जब धरती में पाप, दुराचार, गी हत्या, ब्राह्मण का अपमान होता हैं तो

भगवान जन्म लेकर समस्त पापो का हरण करते हैं। महाराज ने कहा कि भगवान के सीसीटीवी कैमरे से डरिए। उनका कैमरा हर जगह लगा है जिसमें हमारे सारे कर्म रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसलिए अपने कर्म पर

हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिस गाय के पीछे राम-कृष्ण नगे पैर भागते थे आज वो कूड़ा खाने के लिए मजबूर हैं। गौ माता को राष्ट्र माता और भारत को हिंदूराष्ट्र घोषित करना चाहिए।



बिना रजिस्ट्रेशन घरों में पल रहे कुत्ते, करीब 10,000 पालतू कुत्ते, रजिस्टर्ड केवल 1350

कुत्तों के आतंक बढ़ने के बाद सरकार ने निर्देश दिए थे कि पालतू कुत्ते, बिल्ली आदि का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, पर इस नियम का नहीं हो रहा पालन

नसबंदी पर हर साल लाखों के खर्च के बाद भी इनकी आबादी नहीं हो पा रही नियंत्रित
सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

भोपाल सहित प्रदेशभर में कुत्तों के आतंक बढ़ने के बाद सरकार ने निर्देश दिए थे कि पालतू कुत्ते, बिल्ली आदि का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। लेकिन राजधानी भोपाल में ही सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2019 की जनगणना के अनुसार राजधानी में करीब 10,000 पालतू कुत्ते हैं। हालाँकि नगर निगम में महज 1350 कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा करीब दो लाख आवारा कुत्ते हैं। इनकी नसबंदी पर हर साल लाखों के खर्च के बाद भी इनकी आबादी नियंत्रित नहीं हो पा रही।

नगर निगम के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राजधानी की हर कॉलोनी और कई मॉर्चियों, अफसरों के घरों में कुत्ते पले हुए हैं। अधिकांश विदेशी नस्ल के हैं। ऐसे डॉग्स की जानकारी इकट्ठा करने और इनसे लोगों को होने वाली दिक्कतों पर नियंत्रण

के लिए सरकार ने अनिवार्य तौर से रजिस्ट्रेशन कराने के नियम भी बनाए हैं। इसके बाद भी शहर में 1350 से कुछ अधिक डॉग्स को पालने का लायसेंस ही इनके मालिकों को पास है। यह स्थिति तब है जब कुत्ता मालिकों पर पेनाल्टी लगाने का नियम है और पेट डॉग्स के हमलों के मामले सामने आ चुके हैं। नियम है कि पशु चिकित्सक की ओर से जारी सर्टिफिकेट भी देना होगा कि उसे कोई संक्रमण नहीं है और वह परिसर में रखे जाने लायक है।

रजिस्ट्रेशन के बाद निगम आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी पशु चिकित्सक की देख रेख में पशु को माइक्रो चिप अथवा टैग या अन्य साधनों से ब्रांडिंग कोड लगवाएगा, इसे पशु स्वामी की विस्तृत जानकारी होगी। कोड को निकाय के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कोडिंग का खर्च भी पशु स्वामी से लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन एक साल के लिए रहेगा, इसे हर वर्ष समाप्ति के 30 दिन के भीतर रिन्यू कराना होगा, ऐसा न कर पाने पर देरी के



लिए प्रत्येक दिन रजिस्ट्रेशन फीस की दस फीसदी की दर से पेनाल्टी लगाई जाएगी। कोड के साथ या बिना खुले में घूमते मिले पशु को निकाय के अधिकारी जब्त करेंगे, कांजी हाउस में रखेंगे, जब्त करने के एक हफ्ते के भीतर मालिक को दावा करना होगा, ऐसा न होने पर उसका उपयुक्त रीति से निपटान किया जाएगा। कोई ब्रांडेड पशु दो बार से ज्यादा आवारा भटकते पाया जाता है को उसके मालिक को सात दिन में जवाब देने का नोटिस दिया जाएगा, इससे संतुष्ट न होने पर लायसेंस रद्द करने के साथ ही 100 से 500 रुपए की पेनाल्टी वसूली जाएगी।

लायसेंस का प्रावधान 15 साल से: भोपाल नगर निगम पालतू कुत्तों का लायसेंस बीते 15 साल से बना रहा है। अब तक 1350 से अधिक लायसेंस जारी किए जा चुके हैं।

यह पेट डॉग्स की वास्तविक संख्या के मुकाबले काफी कम है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने मप्र नगरपालिका (रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण) नियम 2023, फरवरी 23 में अधिसूचित किए थे। इसमें स्पष्ट तौर से कहा गया कि नगरीय निकाय की सीमा में रखे या लाए गए प्रत्येक पशु के स्वामी इन नियमों के नोटिफाइड होने के तीन महीने के भीतर या शहर में लाने के सात दिन के अंदर, पशु के रजिस्ट्रीकरण के लिए संबंधित अधिकारी को आवेदन करेगा। ऐसा न करने पर पशु मालिक पर रजिस्ट्रेशन फीस की दस गुना पेनाल्टी लगाई जाएगी। नियमों के मुताबिक पशु के खतरनाक या आक्रामक होने की शिकायत मिलने पर उसके मालिक को नोटिस देकर सात दिन में जवाब मांगा जाएगा। इससे संतुष्ट न होने पर नया नोटिस जारी करते हुए तीन दिन में पशु को उचित नियंत्रण में रखने का निर्देश देंगे। इस पर अमल नहीं करने की स्थिति पशु को नीलाम कर दिया जाएगा।

बुधनी रेलवे माल गोदाम पर सीमेंट रेक के साथ इनवर्ड रेक मूवमेंट का शुभारंभ

नर्मदापुरम। एस एम एच कारपोरेशन इटारसी द्वारा बुधनी मालगोदम पर सीमेंट रेक के साथ इनवर्ड रेक मूवमेंट की शुरुआत की है, इसके पूर्व भी एस एम एच कार्रपोरेशन द्वारा बागड़ा तबाह अन्य स्टेशनों पर इसकी शुरुआत की जा चुकी है। कारपोरेशन के डायरेक्टर अर्पित अग्रवाल ने बताया कि इससे रोजगार के नये अवसर तो मिलेंगे ही, ट्रंस्पोट इंडस्ट्री का व्यापार भी बढ़ेगा, श्री अग्रवाल ने बताया कि मूवमेंट की शुरुआत होने से खाद एवं अन्य सीमेंट कंपनियों के लिए



भी अच्छे अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। पूर्व में भी एस एम एच ट्रेडिंग कारपोरेशन के डायरेक्टर अर्पित अग्रवाल ने बागरातवा एवं अन्य स्थानों पर भी ऐसे

ही पहल कर रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराए हैं। अर्पित अग्रवाल ने बताया की इनवर्ड रेक मूवमेंट से वेयरहाउस मालिकों को भी मिलेगा लाभ। इस अवसर पर बुधनी रेलवे के अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित थे।

अर्पित अग्रवाल का कहना है की निकट भविष्य में बुधनी रेलवे के अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित थे।

यदि इटारसी माल गोदाम स्थांतरित होता है तो सीमेंट व खाद कंपनियों के लिए कार्य करने के लिए बुधनी पर्सोदीदा स्टेशन साबित हो सकता है।

धार्मिक स्थलों के विकास से ओर बढ़ेगी संख्या: शुक्ला

प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ 10 गंतव्यों में से पांच गंतव्य धार्मिक स्थल उज्जैन, मैहर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर और सलकनपुर हैं। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला के मुताबिक कई लोग धार्मिक स्थलों पर जाकर मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। धार्मिक स्थलों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। यह स्थल प्राचीन इतिहास, वास्तुकला और संस्कृति का अद्भुत मिश्रण होते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक, ओंकारेश्वर में एकात्म धाम जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं ने भी प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मदद की है। श्री शुक्ला के अनुसार, सलकनपुर में देवी लोक, ओरछा में राजा राम लोक, छिंदवाड़ा में हनुमान लोक, चित्रकूट में श्रीराम वनगमन पथ जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूर्ण होने के बाद निश्चित ही प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में ओर वृद्धि होगी।

वर्ष-पर्यटकों की संख्या

2023-	11,21,29,094
2022-	3,41,38,757
2021-	2,55,95,668
2020-	2,14,00,693
2019-	8,90,35,097
2018-	8,46,14,456
2017-	5,88,62,584

प्रदेश के टॉप-10 गंतव्य

गंतव्य-	पर्यटकों की संख्या
उज्जैन-	52841802
मैहर-	16849000
इंदौर-	10119030
चित्रकूट-	9001126
ओंकारेश्वर-	3475000
जबलपुर-	2669869
सलकनपुर-	2565000
नर्मदापुरम (पंचमढ़ी, मढ़ई,	नर्मदापुरम, आदमगढ़)-
2283837	रायसेन (भीमबेटका, सांची, भोजपुर)-
2137058	भोपाल-
1950965	

पानी, उम्मीद और सशक्तिकरण, सुनीता की दृढ़ता की कहानी

भोपाल। हर माँ अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर और शिक्षा के लिए एक बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का सपना देखती है, लेकिन सुनीता के लिए सच्चाई बिल्कुल ही विपरीत थी। सुनीता जीवनभर मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के दूरवर्ती आदिवासी गांव में रही, जहाँ उसे मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती थीं जिसके कारण उसका जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। अब उसकी 11 वर्षीय बेटी सपना भी एक ऐसे ही भविष्य का सामना कर रही है। सुनीता आर्थिक रूप से वंचित परिवार से है। अपनी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद शारी के बाद उसे एक बेहतर जीवन की महत्वाकांक्षा थी। हालांकि, उसके सपने चकनाचूर हो गए जब कम उम्र में ही उसके पति की मृत्यु हो गई और उसके बच्चों के पालन-पोषण की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसके जीवन की त्रासदी जारी रही और एक भयंकर दुर्घटना में उसके बड़े बेटे की मौत हो गई। बिना किसी सहारे के अब इस परिवार को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। घर चलाने का पूरा बोझ अब सुनीता के कंधों पर था। उसके पास अपनी छोटी बेटी को अकेले घर छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था और उसे पानी लाने के लिए हर दिन छह किलोमीटर चलना पड़ता था। छोटी उम्र में ही सपना को खाना बनाना, कपड़े धोना, घर साफ करना और घर के अन्य

काम करने पड़ते थे जिस वजह से एक होनहार छात्रा होने के बावजूद वह पढ़ाई नहीं कर पाती थी। सुनीता जानती थी कि उसकी बेटी सपना स्कूल जाना चाहती है, लेकिन घर की कठिन परिस्थितियों के कारण उसे कई जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ रही थीं। आखिरकार, सुनीता और सपना जैसे सैकड़ों परिवारों को तब बड़ी राहत मिली जब आनंदना कोका कोला इंडिया फाउंडेशन ने हरीतिका के साथ मिलकर गांव में पानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण काम अपने हाथों में लिया। पानी की उपलब्धता ने पानी की कमी के कभी खतम न होने वाले चक्र से गांववासियों को मुक्त कर दिया, जिसके कारण शिक्षा और कमाई के अन्य अवसरों सहित अन्य रूचियों को पूरा करना और रोजगार करना उनके लिए संभव हो पाया।

पानी लाने के लिए सुनीता को फिर कभी घर के बाहर नहीं जाना पड़ा और वह अपने घर की जिम्मेदारियाँ निभाने लगी, जबकि उसकी बेटी पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगी। सपना ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, हमारे गांव में एक बड़ी टंकी की निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से मेरे घर में नल में मुझे पानी मिलता है। अब मेरी माँ और भाभी को पानी लाने के लिए घर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम लोग आपस में काम बांट लेते हैं। आखिरकार मैं स्कूल जा सकती हूँ और अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ।





सम्पादकीय जिम्मेदारी बनाम औपचारिकता

चुनाव आयोग को लेकर आज जितने सवाल उठाए जा रहे हैं, उतने शायद ही पहले कभी उठाए गए हों। इस बार बड़ा सवाल उठा, उसके द्वारा करीब एक सप्ताह बाद बढ़ाए गए मतदान के आंकड़ों पर। सवाल लाजिमी है। इतने सालों से चुनाव ईवीएम से ही होता आ रहा है, लेकिन चौबीस घंटे से ज्यादा मतदान के आंकड़ों को एकत्र करके घोषित करने में नहीं लगे। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया है।

चुनाव आयोग की भूमिका क्या सही में संदिग्ध हो गई है? मतदान के आंकड़ों को लेकर जो चर्चा अब चल रही है, उसका सार तो यही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दूसरे दिन सुबह तक जो आंकड़े मतदान के आए हों, कुछ दिन बाद उसमें एक करोड़ वोट बढ़ जाएं। यानि सीधे-सीधे बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई हैं। आशंका पहले से ही थी, लेकिन अब साफ-साफ समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग के ये आंकड़े प्रायोजित हैं।

विपक्षी नेताओं के आगे तो स्वाभाविक रूप से आएंगे ही, आ रहे हैं, लेकिन आज उनकी सुनता कौन है। यहाँ लोकतंत्र जैसा कुछ बचा ही नहीं दिख रहा है। ले-देकर थोड़ी बहुत उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। मीडिया की दुंदुभि तो सबको पता है। नब्बे प्रतिशत मीडिया निरवास खो चुका है। आम जनता भले ही कुछ बोल नहीं रही, लेकिन समझ तो सब रही है। देखना होगा कि वोट बढ़ने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का क्या नजरिया रहता है।

बात चुनाव आयोग की ही है, तो उसकी निगाह विपक्ष पर ही अधिक रहती है। स्वाभाविक है, लेकिन उसने चौंकाते हुए देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के अध्यक्षों को आचार संहिता के बाहर जाने के लिए चेताया है। आदेश पर और चाहे जो भी कहा जाए, उसके औचित्य पर सवाल नहीं किया जा सकता। चिंता की बात तो यह है कि सत्तारूढ़ दल और सबसे बड़े विपक्षी दल के नेतृत्व को यह समझाने की जरूरत पड़ रही है कि सांप्रदायिक भाषणों और संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयान नहीं दिए जाने चाहिए।

यह कोई नया मामला नहीं है। चुनाव आयोग ने एक महीने पहले ही शिकायत मिलने पर भाजपा और कांग्रेस के अध्यक्षों को नोटिस देकर आगाह किया था कि वे अपने स्टार प्रचारकों से भाषण के दौरान सावधानी बरतने को कहें। हालांकि तब आयोग के रैस्पॉन्स को कमजोर इस मायने में कहा गया था कि शिकायत तो पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ थी, लेकिन नोटिस सीधे इन दोनों नेताओं के बजाय पार्टी अध्यक्षों को भेजा गया।

चुनाव आयोग के अब तक के चलन को देखते हुए यह तरीका नया था। भाषण किसी और का, शिकायत किसी और की हो रही है और आयोग किसी और को नोटिस या समझाइश दे रहा है। लेकिन इसका हल तो कोई निकला ही नहीं। सवाल-जवाब के क्रम में समय बीतता रहा और अब जब चुनाव आयोग का आदेश आया है तो पांच चरणों की वोटिंग हो चुकी है और छठे चरण का प्रचार भी समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर सातवें और आखिरी चरण का प्रचार ही बचा है।

फिर भी, चुनाव आयोग ने शिकायतों पर जो स्टैंड लिया, उसमें गड़बड़ी नहीं थी। जिस तरह के तीखे सांप्रदायिक मुद्दे इस बार चुनाव प्रचार में छाप रहे, वे उचित नहीं कहे जा सकते। संविधान बदले जाने का जो आरोप विपक्ष ने जोर-शोर से उठाया उसके औचित्य पर भी सवाल उठने लाजिमी हैं। खासकर इसलिए कि संविधान में संशोधन शुरू से होते रहे हैं, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार साबित किया है।

आयोग को इस अनुभव की रोशनी में भविष्य की अपनी कार्यशैली पर पुनर्विचार करना चाहिए।

और यही कारण है कि चुनाव आयोग सवालों के घेरे में बना हुआ है। का वर्षों जब कृषी सुखाने। यानि जब चुनाव पूरे होने को हैं, तब हम सावधान कर रहे हैं। इस बार नेताओं के बयान लगातार बदले हैं। सत्तापक्ष की तरफ से तो भाषा के स्तर को ध्यान में रखा ही नहीं गया, ऐसा लगता है। और चुनाव आयोग भी तभी जागता है, जब उसके पास शिकायतें पहुंचती हैं। फिर आपने जो पर्यवेक्षक और प्रभारी तैनात किए हैं, वो किस लिए हैं? यही नहीं, आयोग को अक्सर सत्तापक्ष की शिकायतों को गंभीरता से लेते देखा गया है। विपक्ष की शिकायतें दमदार होने के बावजूद उन पर कोई खास एक्शन लिया नहीं गया।

शायद यही कारण है कि आयोग ने दोनों प्रमुख पार्टियों को नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी की इतिथी कर ली है जो जिम्मेदारी आयोग की होना चाहिए, वो उन पार्टियों के अध्यक्षों से अपेक्षा कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि पार्टियों के तमाम स्टार प्रचारक नेताओं का कद अध्यक्षों से कहीं बड़ा है। ऐसे में वो उन कद में बड़े नेताओं को क्या समझाइश दे पाएंगे, यह समझा जा सकता है। ऐसा लगता है, मानो चुनाव आयोग ने यहां भी खानापू्र्ति कर दी, कि हमने तो बड़ी पार्टियों को फटकार लगाई, असर पड़े या न पड़े। तब तक चुनाव खत्म। जय राम जी की।

वैध हो जाने की वृत्ति बढ़ाती, अवैध करने की प्रवृत्ति

सरयसुत मिश्रा

क्या ऐसा कहा जा सकता है, कि अवैध काम करने की प्रवृत्ति गवर्नेस ही बढ़ाती है. बहुमत की जुगाड़ में अवैध को भी वैध बनाने की राजनीतिक सोच अंततः किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचती है. रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान का लक्ष्य और संघर्ष है. सब मकान बनाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं. क्रय शक्ति के अभाव में मकान का सपना पूरा करने के लिए इंसान ऐसे कॉलोनाइजर के कुचक्र में फंस जाता है, कि अवैध कॉलोनी में भी रहने के लिए मजबूर हो जाता है.

कॉलोनाइजर बिना वैधानिक प्रक्रिया पूरी किए और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किए कॉलोनियां बनाकर लोगों को ठग लेते हैं. रहवासी पैसे खर्च करके भी कष्टपूर्ण जीवन गुजारता है. यहीं से राजनीति शुरू होती है. अवैध कॉलोनी के निवासियों को राहत देने के नाम पर अवैध कॉलोनी को वैध बनाने का फरमान शुरू होता है. यह केवल मध्य प्रदेश का विषय नहीं है, लगभग पूरे देश में ऐसे ही हालात हैं.

मध्य प्रदेश में तो पिछले विधानसभा चुनाव के पहले अवैध कलानियों के नियमितीकरण का कानून बनाया गया. नियमितीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई, लेकिन बीच में रुक गई. नई सरकार के गठन के बाद ऐसी सुगबुगाहट शुरू हुई है, कि अवैध कॉलोनी को वैध नहीं बनाया जाएगा, बल्कि अवैध काम करने वाले कॉलोनाइजर को दंडित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव अगर अवैध कॉलोनि्यों के मामले में ऐसा रख अपना रहे हैं, तो निश्चित रूप से शहरों के सुनियोजित विकास, बेहतर बुनियादी सुविधाओं और बेहतर पर्यावरण बनाने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम होगा. गवर्नेस की यह शैली केवल एक मामले में प्रभावकारी नहीं रहेगी, बल्कि हर सेक्टर में अवैध काम करके मोटी रकम कमाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी. गलत काम करने वाला दंडित होगा. इसका भय ऐसे ताकतों को अवैध काम करने से रोकेंगा. सिस्टम में भ्रष्टाचार भी

–राकेश दुबे

एक घटना – पुणे में अमीर बाप के बिगड़ैल अल्पवयस्क बेटे ने शराब के नशे में दो युवा इंजीनियरों को रौंदने के बाद जिस तरह आनन–फानन में जमानत हासिल की, उसने तमाम सवालों को भी जन्म दिया है। दुर्घटना की त्रासदी,इन सवालों की जड़ में न्यायिक विवेक भी आ गया है। दुस्साहस देखिये कि दो करोड़ रुपये से अधिक महंगा विदेशी कार को सड़क पर यह किशोर दो सौ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा रहा था। उस धनी बाप के नशेड़ी बेटे को पुणे की सड़कों में रोकने वाला कोई नहीं था। उसने कई जगह दोस्तों के साथ शराब पार्टियां निबटाने के बाद अपनी पोर्श कार को इतनी अनियंत्रित गति से दौड़ाया कि मोटरसाइक्ल सवार दो इंजीनियरों को मौत की नौद सुला दिया। संयोग से दोनों इंजीनियर मध्यप्रदेश के ही थे।

इस मामले में सोशल मीडिया पर आक्रोश का लावा तब फूटा जब 17 साल कुछ महीनों की उम्र वाले अभियुक्त को किशोर होने के नाते कुछ ही घंटों

रुकेगा.

जिस तरह से कर्ज माफी ने सरकारों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है, इसी तरह से अवैध कॉलोनी को वैध बनाकर नियमित करने के सरकारी प्रयास बेहतर शहरों के सपने को मौत के घाट उतार देंगे. शहरों में बुनियादी सुविधाओं और

नागरिकों के लिए कॉलोनी विकास के कामों को राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही समाधान किया जाना चाहिए. पूरा सरकारी सिस्टम जिस पर गलत काम रोकने की जिम्मेदारी है, वही जाने–अनजाने गलत काम को अंजाम तक पहुंचाने का दूल बन जाता है.

राजनीतिक कारणों से सरकारें बहुमत पाने के चक्कर में ऐसे गलत कामों को वैधता देने में भी संकोच नहीं करतीं. शहर को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं लागू हुई हैं. लेकिन शहर के किसी भी कोने में झुग्गियों में कोई कमी नहीं आई है. झुग्गियों के स्थान पर पक्के मकान बनाने की योजनाओं के अंतर्गत बड़े–बड़े भवन बने. झुग्गी वालों को इसके पट्टे भी दिए गए, उस पर कब्ज़ा भी दिया गया. लेकिन झुग्गियां फिर भी कम नहीं हुई.

एक ही दल की सरकार में अवैध कॉलोनी को नियमित करने को लेकर दो विचार सामने आए हैं. पूर्व के मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनि्यों के नियमितीकरण की घोषणा की थी. कानून भी बनाए थे. अब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव इसके विपरीत अवैध कॉलोनी को नियमित करने को उचित नहीं मान रहे हैं. किसी भी अवैध काम को वैध करने का विचार कभी भी उचित नहीं हो सकता. जब तक कि नियम प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया जाए, जिसने भी गलत काम किया है, उसे दंड ना दिया जाए. डॉ.

यहाँ फ़ैसला - शून्य सहिष्णुता होना था

में जमानत दे दी गई। दो परिवारों के उम्मीदों के चिराग बुझ गए और किशोर न्यायालय ने अभियुक्त को कुछ निर्देश देकर ही छोड़ दिया ।

यह विषय रोष का विषय बना रहा है कि किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत देते वक्त उसे महज दुर्घटना पर निबंध लिखने, 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने तथा मनोचिकित्सक से शराब की लत का इलाज कराने को कहा। इन शर्तों को सुनकर सोशल मीडिया पर गंभीर अपराधों में लिप्त किशोरों को वयस्कों की तरह दंड देने की मांग तेज हुई। फिर जब इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हुई तो अभियुक्त किशोर के अरबपति बिल्डर पिता और नाबालिगों को शराब परोसने वाले होटल के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। सामाजिक जागरूकता को पहल रंग लायी और चुनावी माहौल में तुरत-फुरत कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री की सख्त कार्रवाई के निर्देश से लोगों में सकारात्मक संदेश गया। साथ ही पीड़ित से लोगों में विश्वास जगा कि कानून काम करता है चाहे आरोपी कितना भी ताकतवर क्यों न हो। निस्संदेह, ऐसे

वैध हो जाने की वृत्ति बढ़ाती, अवैध करने की प्रवृत्ति

मोहन यादव को इस बात के लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए कि वह अस्तित्व के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं.

अवैध कॉलोनी के निर्माण को सख्ती के साथ रोका जाना चाहिए, जो कॉलोनी पहले से बन गई हैं, उनमें बुनियादी

सुविधाओं का विकास करना चाहिए. इसके लिए इन अवैध कॉलोनिनों के निर्माता कॉलोनाइजर्स पर दंड निरूपित करना चाहिए. इन कॉलोनिनों में जो भी रिक प्लॉट हों उनका सरकार अधिग्रहण करे और उनसे जो धनराशि प्राप्त हो, उससे बुनियादी विकास का काम पूरा करे.

मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की विकास की दृष्टि सैद्धांतिक से ज्यादा प्रैक्टिकल लग रही है. जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तब से कई ऐसी बाधाओं को हटाय़ा है, जिनके कारण लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. राजधानी भोपाल में इक्क़त्तर को हटाने का चुनौतीपूर्ण निर्णय डॉ. मोहन यादव द्वारा ही लिया जा सकता है. इक्क़त्तर खत्म होने से भोपाल के लोगों को बड़ी राहत मिली है. इसी तरीके से रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया को भी कनेक्ट कर दिया गया है.

अक्सर सरकारों में ऐसा देखा जाता है, कि निर्णायक स्तर पर बिना तार्किक कारणों के निजी कारणों से कई बार ऐसे फैसले लिए जाते हैं, जिनके बहुत दूरगामी दुष्प्रभाव शहर और समाज पर पड़ते हैं. फैसले लेते समय समाज की जरूरत और समाज का हित ही सर्वोपरि होना चाहिए. नीतियां और योजनाएं बनाने का आधार केवल जनहित होना चाहिए.

शहरों में कॉलोनिनों का विकास और लोगों को

वैध हो जाने की वृत्ति बढ़ाती, अवैध करने की प्रवृत्ति

घर उपलब्ध कराने की संपूर्ण प्रक्रिया गवर्नेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. इसके लिए कानून-कायदे बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कॉलोनिनों के निर्माण में गड़बड़ियां और सिस्टम के साथ मिलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी एक आम बात हो गई है.

किसी भी कॉलोनी में जरूरी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं. कॉलोनाइज़र, बिल्डर मकान और प्लॉट बेचते समय जो वायदे करते हैं, वह भी अंत में पूरे नहीं होते हैं. रहवासी मजबूर बना रहता है. पिछले सालों में रहवासियों के हित में कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई खास बदलाव नहीं आया है.

रेरा जैसी संस्थाएं भी जमीन पर अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पा रही हैं. कॉलोनी निर्माण में लगी निजी और सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं और पूरा सिस्टम अजीब सी खुशी और ग़म में जीवन गुजरता है. यह क्षेत्र सबसे ज्यादा कमाई का क्षेत्र कहा जा सकता है. इस क्षेत्र में जिसने भी शोषण किया है,अंततः वह भी शोषण का ही शिकार होता दिखाई पड़ता है.

ऐसा लगता है अवैध कॉलोनी के रहवासियों का दर्द मोहन यादव समझते हैं. इसीलिए अपनी पार्टी की पुरानी सरकार के अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण के फैसले को बदलने का साहस कर पा रहे हैं. गवर्नेस में इस तरह का प्रैक्टिकल अप्रोच अगर चलता रहा, तो डॉ. मोहन यादव की सरकार वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान करने में सफल हो सकती है.

पीएम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री, डॉ. मोहन यादव की अनेक बार तारीफ कर चुके हैं. बीआरटीएस तोड़कर और अवैध कॉलोनिनों के मामले में फैसले को पलट कर मुख्यमंत्री ने साबित किया है, कि उनकी दृष्टि जमीन पर है. जमीन की समस्याओं पर उनकी पकड़ और नजर है. और जमीन की समस्याओं के समाधान का उनका प्रैक्टिकल नजरिया है. अवैध कॉलोनाइज़र और इसके लिए दोषी अफसर दंडित होंगे, तो मध्य प्रदेश सरकार महिमार्मंडित होगी.

यहाँ फ़ैसला - शून्य सहिष्णुता होना था

थी। जो कालांतर भविष्य में ऐसी त्रासदियों को टालने में मददगार हो सकती है। अपराध के अनुपात में दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए ।

देश के विभिन्न भागों में भी किशोरों द्वारा तेज रफ्तार वाहन चलाने के तमाम मामले प्रकाश में आते रहते हैं, जिसमें खतरनाक ड्राइविंग के चलते कई किशोरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये घटनाएं यातायात कानूनों को सख्ती से लागू करने और किशोर अपराधियों को दंडित करने के लिये कानूनी ढांचे की समीक्षा की आवश्यकता पर बल देती हैं। निस्संदेह, देश की न्यायिक प्रणाली को इस तरह के मामलों में उचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सही मायनों में अपराधी की उम्र की परवाह किये बिना ऐसे घातक कृत्यों में कई दंड के जरिये मिसाल कायम की जानी चाहिए।इससे जहां जनता का विश्वास बहाल होगा,वहीं हमारी सड़कों पर किशोरों की लापरवाह ड्राइविंग से होने वाली मौतों को भी रोका जा सकेगा। निश्चित रूप से इससे दुर्घटनाओं में मारे लोगों के परिजनों को भी न्याय मिल सकेगा।

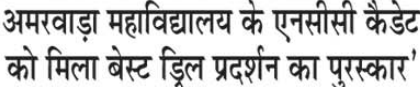
इब्राहिम रईसी को यूं ही नहीं कहा गया था तेहरान का कसाई

भी हुए। राजनीतिक कैदियों से पारिवारिक मुलाकातें निर्लंबित कर दी गई और उन्हें फांसी की कोई जानकारी कभी नहीं दी गई। रिश्तेदार नियमित मुलाकात के दिनों में जेल जाते थे लेकिन जेल प्रहरियों द्वारा उन्हें लौटा दिया जाता था। कुछ लोग जेलों में कपड़े, दवाइयां या पैसे इस उम्मीद से लाते थे कि उन्हें अपने कैद रिश्तेदारों से एक हस्ताक्षरित रसीद मिल जाएगी जो यह संकेत देगी कि वे अभी भी जीवित हैं। फांसी के शिकार लोगों को सामूहिक कब्रों में दफनाया गया और परिजनों को उनकी कब्रों को लेकर भी कुछ नहीं बताया गया। बाद में यह आदेश दिया

गया की अंतिम संस्कार या कोई अन्य शोक समारोह आयोजित नहीं करेंगे। इब्राहिम रईसी कहते थे कि जो अल्लाह से युद्ध करते हैं, उन पर दया निरखना मूर्खतापूर्ण है। साल 1999 में मानवाधिकार पर आधारित एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों के लिए जिन लोगों को फांसी दी गई, उनमें से कई वास्तव में राजनीतिक असंतुष्ट थे।

यही नहीं सामूहिक कब्रों की वास्तविक संख्या छिपाई गई और ईरानी अधिकारियों ने अवशेषों के स्थान को छिपाने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दफन रजिस्ट्रारों से अधिकांश पीड़ितों के नामों को भी बाहर कर दिया। इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति बने तो हिजाब को लेकर सख्त पाबंदी के चलते देश भर से खूब विरोध प्रदर्शन हुए। नैतिकता पुलिस ने कई महिलाओं को कोड़े से मारने की सजा दी। सैकड़ों महिलायें मारी गईं। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में सड़कों पर रईसी के सम्मान में सहज रूप से बड़ी संख्या में भीड़ नहीं जुटी। तमाम प्रतिबंधों के बाद भी लोगों ने रईसी पर तंज किए और खुशी का इजहार भी किया। कहते हैं कि तानाशाहों की मौत पर सरकारी मातम होते हैं और खुशियां दिल में होती हैं। इरानियों का हाल कुछ ऐसा ही है। लोगों के मन में रईसी के कृत्यों लिए बहुत गुस्सा और असहनीय दर्द है और इससे ईरान में मानवाधिकारों की रक्षा की उम्मीद भी बढ़ी होगी।





शिक्षा ही एकमात्र मूल्यवान संपत्ति है जो समग्र जीवन को व्यवस्थित करती है: ब्रण्बसंत महाराज



यादगार रहा समाधि

वीतराग भवन में बाल

छेंदवाड़ा। मध्य प्रदेश की धर्म गरी छिंदवाड़ा के वीतराग भवन में मकल जैन समाज के लिए मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा बाल ब्रह्मचारी ईश्वरजी सुमनप्रकाशजी जैन के गंगल सानिध्य में लगाया गया नौ देवसीयी समाधि साधना प्रशिक्षण शिविर एवं न्यायिक सम्मेलन विविध उपलब्धियों के साथ यादगार एवं ऐतिहासिक रूप से साआनंद संपन्न हुआ।

फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने बताया शिविर में पूरे देश से ब्रह्मचारी भाई बहनों के साथ श्रावक श्राविकाओं का छिंदवाड़ा आगमन हुआ और सभी ने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक सम्यक समाधि सहित क्षमक एवं न्ययिक का स्वरूप समझा और उस अनुसार जीवन जीने का संकल्प लिया। शिविर में बाल ब्रह्मचारी वरिष्ठ शास्त्री एवं महेंद्र जैन ने बालवाकाचार के आधार पर जीरोपेथी के



मध्यम से अहिंसा जीने की कला ए उपचार को बताया इस अवसर पर थारी बाल र बहनजी ने बहुत जिनागम का स और दिगंबर बताकार मुनिराजी इस अवसर महिला मंडल के साथ शिविर श्रीमती सनीसी

बिछा रखा था। दिल्ली से चल रही सीबीआई विजिलेंस जांच में सामने आया है कि अक्सर जांच के नाम पर रिश्ते की राशति देत देते हैं। घूस लेकर कॉलेजों को उपयुक्त कर्सीफिकेट बना दब साबित करा है कि पुराने प्रदेश वे छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ इन कॉलेजों में खिलवा रहे होंगे जिन पर शोक लगाना अनावश्यक है।

एनएसयूआई खिलाड्धख नज़ात सिंह ठाकुर की सहभागिता उपांगत एनएसयूआई नगर अध्दध समर्थ मैद के नेतृत्व संपी गये ज़ापन में राज्यपाल से सम्पूर्ण ब्लैक लिस्टिंग नाँसों माँग की है। पुराने दिल्ली सीबीआई से जांच करार की माँग की है। ज़ापन सौंपते समय प्रमुख रूप से निगम ग्रामीण अध्दध पीपुष शांती, औचित मेहराएं अंडूल शमा लोहसन, तालिख शाम, नयन एवं शहर एनएसयूआई वै पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जिला गृह, गैहू, गायत्री यज्ञ उपासना जिला प्रभारी अरुण पराइकर द्वारा बताया गया कि 23 मई 2024 बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर विश्व कल्याण पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यवर्धन संस्था के साथ मिलकर प्रत्येक विकासखंड के सभी गांवों में गायत्री परिवार एवं संस्थाओं के माध्यम से, गायत्री परजनों के माध्यम से घर घर जाकर, ऑनलाइन बुद्ध मंत्र, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से यज्ञ कर्मकांड का संचालन शांतिकुंज हरिद्वार के मनीषियों द्वारा किया गया इस पावन अवसर पर शांतिकुंज हरिद्वार से गायत्री परिवार प्रमुख आदर्शगोप श्रेष्ठय डॉ. प्रणव पंड्या हरिद्वार याह अवसर उद्घोष में बताया की गायत्री यह वैभारिक विष्णुक्रता की दूर कर देता है एवं यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण का पर्यावरण होता है पुरतन काल में जब विश्व परिसिद्ध, टीका नही लगाया जाता समुलन को कामना के साथ इस आयोजन को लेकर गायत्री परिवार मुखोद्धार के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया जिसमें स्कूल के बच्चों धार्मिक संस्थाओं सामाजिक संस्थाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उत्साह और उमंग के साथ अपने-अपने घरों में यज्ञ कर सबके मंगलमय जीवन की प्रार्थना की गई।

इस अवसर अवसर पर जिला समन्वयक दिनेश देशमुख द्वारा बुद्ध पूर्णिमा पर छिदवाजा जिले में ऐतिहासिक आयोजन आज संपन्न हुआ है एतिहासिक गायत्री परिवार सहकारियों में गायत्री परिवार सहकारियों सामाजिक संगठन धार्मिक संगठन के सहयोग हेतु हम आभारी रहेंगे आप सबका यह योग्य निष्ठित रूप से इस वैश्विक संकट को दूर करने के लिए कारगर सिद्ध होगा। इस अवसर पर संस्थान ने एक एक वृक्ष को लगाने का संकल्प लिया।

यमकाने के लिए की गई है। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने सरकार के आदेश की आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा के दो दशक के शासनकाल में भी धीरे धीरे करके सारे कर्मचारियों संगठनों को खत्म करनेए कानूनी झगड़ों में डल्ला देने की नीति अपनाई जाती रही है, जो संगठन इससे बचे रहे खत्म उन्हें इस पकड़तए और पहली नजर में ही अवैधानिक आदेशों के जरिये समाप्त किया जा रहा है। वासुदेव मुखर्जी के अधीन आने वाले विभाग द्वारा ऐसा किया जाना स्पष्ट करता है कि यह भाजपा सरकार की सोची समझी नीति का हिस्सा है। लोकतंत्र के नाकी आयामों को सिकोड़ने के बाद अब कर्मचारियों के संगठन बनाने के संवैधानिक अधिकारों को भी बाधित करने की साजिश रची जा रही है। वासुदेव शर्मा ने याद दिलाया है कि जिन संगठनों की मान्यता समाप्त किया गया है वे आधी सदी से भी अधिक समय से कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। उनके साथ इस तरह की धड़ाधड़ कार्यवाही, उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय तक न देना पूर्वाग्रही मानसिकता का उद्धारण है।

त्वरित टिपण्णी

जी. के. छिब्रार

अनुच्छेद 370 की समाप्ति

संविधान सम्मत, पुनर्विचार

याचिकायें निरस्त

संविधान पीठ का निर्णय

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने वो सभी पुनर्विचार याचिकाएं निरस्त कर दी है जिसने संविधान पीठ के 11 दिसम्बर 2023 के सर्वसम्मत निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। संविधान पीठ ने 5 अगस्त 2019 के अनुच्छेद 370 एवम 35 ए की समाप्ति के सरकार के निर्णय को संविधान सम्मत ठहराया था।

पीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाओं में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके कारण 11 दिसम्बर 23 के सांविधान पीठ के निर्णय पर पुनः मौखिक सुनवाई की जाए। याचिकाओं के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है की समस्त उठाए गए सवालों का निष्कर्ष 11 दिसम्बर 23 के निर्णय में दिया जा चुका है।

यह उल्लेखनीय है कि आजादी के बाद 70 वर्ष तक जम्मू कश्मीर वोट बैंक एवम अलगाववादी ताकतों की राजनीति का शिकार रहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अनुच्छेद 370 एवम 35 ए की आड़ में कश्मीर को अलग थलक बनाए रखा जिसमे काँग्रेस की भूमिका भी सक्रिय सहयोगी की रही।

कोई भी सरकार संविधान के अस्थाई अनुच्छेद को छूने का साहस नहीं कर पा रही थी लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में यह मुद्दा वर्षों से रहा जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राजनैतिक कौशल एवम इच्छा शक्ति ने यह क्रांतिकारी कदम उठाया और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को नई दिशा दी जिसका परिणाम गत 5 वर्षों में काश्मीर घटी में आतंकवाद समाप्ति पर है पर्यटक भारी संख्या में जा रहे है व्यापार बड़ा है अमन चैन है। संविधान पीठ के निर्णय में कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए आयोग बनाने का निर्देश दिया था तथा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा शीघ्र प्रदान करने का भी उल्लेख किया था दलितों को सम्पूर्ण अधिकार मिलेंगे आरक्षण मिलेगा।

पुनर्विचार भी अब निरस्त हो गई है अब राज्य में शीघ्र विधान सभा के चुनाव होंगे ऐसी आशा की जा सकती है लोकसभा के चुनावों में कश्मीर में भरी रिकॉर्ड मतदान हुवा है जो शुभ संकेत है जनतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हुई है।



मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की 46 वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज रेल कोच स्टैण्ड में आरुणि संस्था के बच्चों को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया गया। यहां साथ ही प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिव शेखर शुक्ला तथा निगम के प्रबंध संचालक डॉ. इलैया राजा द्वारा बच्चों को उपहार भी वितरित किए गए।

कमजोर प्रदर्शन वाले युवा कांग्रेस के पदाधिकारी बदले जाएंगे, शीघ्र ही बनेगी नई टीम



नहीं कर पाएगा, उसकी जगह किसी अन्य ऊर्जावान नौजवान साथी को अवसर दिया जाएगा। दूसरे दिन की चर्चा में मितेन्द्र ने यह भी कहा कि इस सोच के साथ काम नहीं करना है कि अब अगला चुनाव पांच साल बाद होगा। संगठन का सोच हर दिन चुनाव लड़ने जैसा होना चाहिए।

उन्होंने कहा-परिवर्तन सबको समझ में आ रहा है कि लड़का काम करने वाला होगा तभी तो मेरी विधानसभा में काम करेगा, उनके जिले में काम करेगा। आज कोई भी ऐसा नाम नहीं देना चाहता जो उनके लिए बोझ बने क्योंकि हर काम की मॉनिटरिंग होने लगी है।

कॉलेज में चुनाव होने चाहिए

मितेन्द्र ने मीडिया से चर्चा के दौरान साफ शब्दों में कहा- कॉलेज में चुनाव बिल्कुल होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा को यह सोच नहीं है कि युवा को आगे बढ़ाए। अगर यह सोच होती तो छात्र संघ के चुनाव होते। ये चुनाव तो एक युवा के लिए निर्णायक भाव और भावनात्मक चुनाव होते हैं। जहां से दुनिया के देश के जो लीडर हैं वो छात्र संघ से निकले। भाजपा से कहना चाहता हूँ कि आप युवाओं को शोषण करना बंद करें। और यह कहना बंद करें कि हमने युवाओं के लिए मुकाम खड़े किए हैं। यह सभी युवाओं को झूठे सपने बेचते हैं। 20 करोड़ नौकरियों का बेचा, भती का सपना बेचा, व्यापम जैसे घोटाले हुए, पटवारी घोटाला, आपने कहा था कि हम भती कैलेंडर बनाएंगे। कहा है वह कैलेंडर? अब यह पूछना पड़ेगा आप युवाओं के साथ कहाँ न्याय का काम कर रहे हैं आप टोटल अन्याय का काम कर रहे हैं।



माधवी राजे की अस्थियां शिप्रा में विसर्जित:दर्शन और पुष्पांजलि के बाद कलश यात्रा निकली, रामघाट पर हुआ पूजन

उज्जैन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया की अस्थियां शुक्रवार को उज्जैन में शिप्रा में विसर्जित की गई। ग्वालियर से आए गए अस्थि कलश को दर्शन के लिए सख्याराजे धर्मशाला पर रखा गया। यहां लोगों ने पुष्प अर्पित किए।

इसके बाद अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। इसके लिए रथ को तैयार किया गया है। रथ पर माधवी राजे सिंधिया का पोस्टर लगाया गया। यात्रा देवास गेट मालीपुरा, कंठाल गोपाल मंदिर होते हुए रामघाट पहुंची। यहां पूजन किया गया।



15 मई को राजमाता माधवी राजे सिंधिया का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। 16 मई को ग्वालियर में छत्री परिसर में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। ग्वालियर से राजमाता माधवी राजे का दूसरा कलश गुरुवार को शिंदे मंडली के सदस्य पांडु रंगा राव

और महल के अधिकारी संग्राम सिंह कदम उज्जैन लेकर आए। यह माधवी राजे की अस्थियों का तीसरा कलश होगा। सिंधिया राजघराने से जुड़े डॉ. विजय त्रिवेदी ने बताया कि यात्रा में सिंधिया राजघराने के लोग शामिल हो सकते हैं।

फर्जी बिल घोटाला खुलने के बाद नगर निगम में गैर जरूरी सतर्कता से परेशानी !

इंदौर । सवा करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला सामने आने के बाद नगर निगम के लगभग हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बहुत सतर्क होकर काम कर रहे हैं। यह सतर्कता काम को लेकर नहीं बल्कि रकयों को बचाने को लेकर है। हालांकि इस सतर्कता के गैर जरूरी काम के कारण अब निगम से जुड़े अन्य विभागों को फाइलें अटकने लगीं।



बोरिंग और स्ट्रीट लाइट के

2200 से ज्यादा कनेक्शन

निगम के इस घोटाले के कारण मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के करीब 5 करोड़ रुपए अटक गए हैं। शहर में नगर निगम द्वारा करीब 2200 बिजली कनेक्शन लिए हुए हैं। यह बिजली कनेक्शन स्ट्रीट लाइट और प्लक्वूप की मोटर चलाने के हैं। इन बिजली कनेक्शन में उपयोग की गई बिजली का हर महीने का करीब 5 करोड़ रुपए का बिल आता है। इस बिल का भुगतान नगर निगम के द्वारा किया जाता है। इस महीने का भी बिल आ चुका है।

नगर निगम की ओर से इसका भुगतान करने के लिए फाइल तैयार कर निगम के ऑडिट विभाग में भेजी गई। ऑडिट विभाग के द्वारा इस फाइल को पास करने से इनकार कर दिया गया है। ऑडिट विभाग ने इस फाइल को निगम की लेखा शाखा में भेज दिया है। विभाग का कहना है कि पहले लेखा शाखा इस फाइल की जांच कर ले, देख ले और अपनी टिप्पणी फाइल की नोटशीट पर दर्ज कर दे। उसके बाद में ऑडिट विभाग को फाइल भेजी जाए।

प्रक्रिया से हटकर कैसे करें काम

इस बारे में लेखा शाखा के अधिकारियों का कहना है कि अब तक की परंपरा के अनुसार विभाग से फाइल ऑडिट विभाग में आती है और वहां से पास होने के बाद वापस विभाग में जाती है। फिर जाकर यह फाइल लेखा विभाग में भुगतान के लिए आती है। अब इस प्रक्रिया से अलग हटकर प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश ऑडिट विभाग के द्वारा की जा रही।

दरअसल नगर निगम के इस फर्जी फाइल घोटाले में ऑडिट विभाग के चार अधिकारी निर्लिखित हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप अब ऑडिट विभाग के अधिकारी इस तरह का कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं। जिससे कि आने वाले समय में उनकी भूमिका पर सवाल उठ सकें। इस सब स्थिति के चलते हुए ही बिजली कंपनी के भुगतान की फाइल अटक गई है।



मंडल 3040 की रोटरी गवर्नर रितु गोवर भोपाल में रोटरी क्लब ईस्ट भोपाल की आधिकारिक विजिट पर आज आई रोटरी क्लब ईस्ट भोपाल के अध्यक्ष संजय दुबे ने क्लब की सेवाओं को रिपोर्ट प्रस्तुत की। गवर्नर रितु गोवर ने क्लब के सेवा कार्यों का भ्रमण भी किया और क्लब के सदस्यों को धन्यवाद दिया।

9 जून को हड़ताल पर रहेंगे स्थाई एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के आवाहन पर प्रदेश भर के हजारों स्थाई कर्मी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपनी प्रमुख मांगों के समर्थन में 9 जून 2024 को हड़ताल पर रहेंगे तथा अबेडकर जयंती मैदान तुलसी नगर भोपाल में धरना देकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे हड़ताल का नोटिस आज स्थाई कर्मियों एवं दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों ने मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि स्थाई कर्मियों को सालाना वेतनमान का लाभ एवं पुरानी पेंशन का लाभ तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने स्थाई कर्मियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उच्च न्यायालय जबर्पुर के

आदेश दिनांक 27 फरवरी 2024 का लाभ देने अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने स्थानांतरण नीति बनाने आकस्मिक मृत्यु होने एवं सेवानिवृत्त होने पर 10 लाख रुपये प्रेजुटी का लाभ देने अनुमान कार्ड की सुविधा देने मेंडिकल सुविधा तथा अवकाश सुविधा सरकारी कर्मचारियों की सामान देने की मांग के समर्थन में प्रदेश भर के स्थाई कर्मी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे ,सरकार लंबे समय से प्रदेश के स्थाई कर्मियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मांगों को संज्ञान में नहीं ले रही है पिछले 8 साल से स्थाई कर्मियों को किसी प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं दिया है ना ही चतुर्थ श्रेणी के 30 हजार पद रिक्त होने के बावजूद भी स्थाई कर्मियों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमित किया जा रहा है।



चिल्ड्रन्स थियेटर अकादमी द्वारा बच्चों के लिए मुखौटा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत बच्चों को कलाकार गयूर कुरैशी उज्जैन मुखौटा सिखा रहे हैं। कार्यशाला का मार्गदर्शन प्रेम गुप्ता द्वारा किया जा रहा है।

खजराना सट्टा कांड में टीआई सस्पेंड, कुछ और पर कार्यवाही होगी

इंदौर। खजराना इलाके में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े नेता के घर चल रहे सट्टे पर कार्रवाई के मामले में खजराना थाने के टीआई सुजीत श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया। उन्हें थाने से हटाकर अटैच किया गया है। बुधवार को डीएसपी के निर्देश पर सट्टे के अड्डे पर दबिश दी गई थी। यहां से बड़ी मात्रा में नकदी जब्त हुई थी। समझा जा रहा कि इस मामले में कुछ और पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी।

था। मंसूरी ने खुद को विधायक (भाजपा) प्रतिनिधि बताकर पुलिस को कार्यवाही से रोकने की भी कोशिश की। लेकिन, पुलिस किसी दबाव में नहीं आई। पुलिस ने मौके से 11 लाख 77 हजार रुपए जब्त कर मंसूरी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी किया। थाना खजराना में अपराध क्रमांक 450 2024 थारा 419 भादवि, द पब्लिक गैबलिंग एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सलीम के विरुद्ध कई प्रकरण दर्ज है। पुरा थाना सट्टे के अड्डे से वाकिफ था। मामले में थाना प्रभारी सुजीत श्रीवास्तव सहित बीट अधिकारी की भूमिका सौंदध्य बताई गई।



कार्यवाही की खजराना टीआई को खबर नहीं

पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता को सूचना मिली थी कि खजराना इलाके के अशर्फी नगर में सलीम मंसूरी में लंबे समय से सट्टा चल रहा है। अफसरों से सांठाठ और विधायक का करीबी होने से इस पर कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस कमिश्नर ने जोन-2 के डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा को कार्यवाही निर्देश दिए। डीसीपी ने परदेशीपुरा एसपी (आईपीएस) नरेंद्र रावत की टीम गठित की और खजराना पुलिस को बताए बगैर छापा मारा।

नर्मदापुरम में गर्मी से 3 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी

आज आधे एमपी में लू का अलर्ट ; ग्वालियर-चंबल की गर्मी मालवा-निमाड़ में शिफ्ट



भोपाल मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। 2-3 दिन से ग्वालियर-चंबल की गर्मी मालवा-निमाड़ की ओर भी शिफ्ट हुई है। इस वजह से इंदौर, उज्जैन, खंडवा, शाजापुर भी भट?टी की तरह तप रहे हैं। यहां तापमान रिकॉर्ड 44 से 46 डिग्री के पार जा पहुंचा है।

गुरुवार को गुना सबसे हॉट रहा। यहां टेम्प्रेचर रिकॉर्ड 46.6 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल, इंदौर और उज्जैन सौजन के सबसे गर्म रहे। ऐसा ही मौसम की शुरुवार को भी बना रहेगा। प्रदेश के आधे हिस्से में लू का अलर्ट भी है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा,

पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट में आंधी-बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। नर्मदापुरम के पवारखेड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज की तीन छात्राओं की तबीयत गुरुवार रात बिगड़ गई। रात 9.30 बजे छात्राओं को हॉस्पिटल स्टाफ जिला अस्पताल लेकर आया। एक छात्रा बेहोशी की हालत में थी। छात्राओं को उल्टी और डिहाइड्रेशन की शिकायत है। इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर राजेश धाकड़ ने बताया कि गर्मी की वजह से छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है। नर्मदापुरम में गुरुवार दिन का तापमान 40.7 डिग्री रह्य।

मालवा - निमाड़ में भी भीषण गर्मी...

भोपाल के सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश सिंह ने बताया कि 4-5 दिन पहले तक एक ट्रफ लाइन तेलंगाना से पूर्वी मध्यप्रदेश तक बनी थी, जो गुजर गई है। ड्राइ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी गुजर रहा था। इस वजह से उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी गर्म हवाएं प्रदेश के उत्तरी हिस्से को ज्यादा प्रभावित कर रही थीं। पिछले 24 घंटे की बात करें, तो राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इस वजह से इंदौर, उज्जैन संभाग में पश्चिमी हवाएं प्रभावी हैं। इस कारण कुछ जिलों में लू का असर है। ग्वालियर-चंबल के साथ मालवा-निमाड़ में भी भीषण गर्मी है। मई के आखिरी तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा।